न्यूज डायरी

व्लादिवोस्तोक शहर बन सकता है रूस और चीन के बीच जंग का सबब

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) मास्को। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगे चीन ने अब एक और मोर्चा खोल दिया है। चीन के सरकारी न्यूज चैनल के संपादक शेन सिवई ने दावा किया है कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर वर्ष 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इस शहर को पहले हैशेनवाई के नाम से जाना जाता था और रूस से एकतरफा संधि के जरिए इसे छीन लिया गया था। दरअसल, व्लादिवोस्तोक शहर की स्थापना के उपलक्ष में चीन में रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट्ट शेयर की थी। इस ट्वीट के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने ट्वीट कर इस शहर को चीन का हिस्सा बताया। इसी विवाद में सीजीटीएन के संपादक शेन सिवई भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि रूसी दूतावास के इस पोस्ट को चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर पसंद नहीं किया गया। व्लादिवोस्तोक का इतिहास 1860 से रहा है जब रूस ने इसे एक सैन्य अड्डा बना लिया।

पीएम राजपक्षे के साथ वार्ता के बाद श्रीलंका के बंदरगाह कर्मियों ने प्रदर्शन समाप्त किया

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) कोलंबो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ बैठक के बाद कोलंबो बंदरगाह के श्रमिकों ने व्यस्ततम बंदरगाह के ''कंटेनर टर्मिनल'' को विकसित करने से रोकने के लिए कथित ष्भारतीय दबावष् के खिलाफ जारी अपने विरोध प्रदर्शन को समाप्त कर लिया। बृहस्पतिवार को श्रमिकों ने कहा था कि अगर सरकार किसी अन्य देश को ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) बनाने की मंजूरी देती है तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। श्रीलंका की पूर्ववर्ती सिरीसेना सरकार ने ईसीटी को विकसित करने के लिए त्रिपक्षीय प्रयास के तहत भारत और जापान के साथ ष्सहयोग ज्ञापनष् (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए थे। ईसीटी 50 करोड़ अमेरिकी डालर के चीन संचालित कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (सीआईसीटी) के पास स्थित है। एमओसी पिछले साल पूरा हो गया था लेकिन टर्मिनल विकास के लिए औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होना बाकी है।

अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे व्लादिमीर पुतिन, संसोधन पास

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) मॉस्को। रूस में हुई हालिया वोटिंग व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक सत्ता में काबिज रह सकेंगे। वहां की जनता ने इस संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन कानून पर जनता की राय मांगी गई थी। इस वोटिंग में जनता ने संसोधन की मंजूरी दी। अब संविधान संशोधन कानून के जरिए पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें छह छह साल के दो अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलना तय है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से वोटिंग स्लो भी हुई। बूथ पर लोगों की भीड़ नहीं लगाई गई। पूरी वोटिंग एक हफ्ते में हो पाई। संविधान में किए गए संशोधनों के लिए जनता को विश्वास में लेने के वास्ते पुतिन ने बड़े स्तर पर अभियान छेड़ा था।

हॉन्ग–कॉन्ग निवासियों को ब्रिटेन का नागरिकता ऑफर, गुस्साया चीन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) लंदन। हॉन्ग–कॉन्ग के नागरिकों को नागरिकता की पेशकश करने के ब्रिटेन के फैसले पर चीन ने नाराजगी जताई है। चीन ने गुरुवार को चेतावनी दी कि ब्रिटेन के इस फैसले का वह इसके श्अनुरूप जवाबश देगा। चीन ने इस हफ्ते ही हॉन्ग–कॉन्ग में नैशनल सिक्योरिटी लॉ को लागू किया है। बता दें कि पहले हॉन्ग–कॉन्ग ब्रिटेन के ही अधीन था। चीन ने कहा है कि वह इस कदम का कड़ा विरोध करता है और इसके हिसाब से कदम उठाने का अधि ाकार रखता है। यही नहीं, चीन ने यह भी कहा है कि लंदन अपने फैसले पर दोबारा विचार करे और श्हॉन्ग–कॉन्ग के मसलों में दखल देने से बचे। चीनी दूतावास ने लंदन में इस बात पर जोर दिया कि हॉन्ग–कॉन्ग में रह रहे सभी चीनी चीन के ही नागरिक हैं।

चीन ने भारत के प्रति अपनाई आक्रामक नीति

रिपोर्ट

अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने एलएसी स्पष्ट करने के प्रयासों को 'रोका'

■यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है

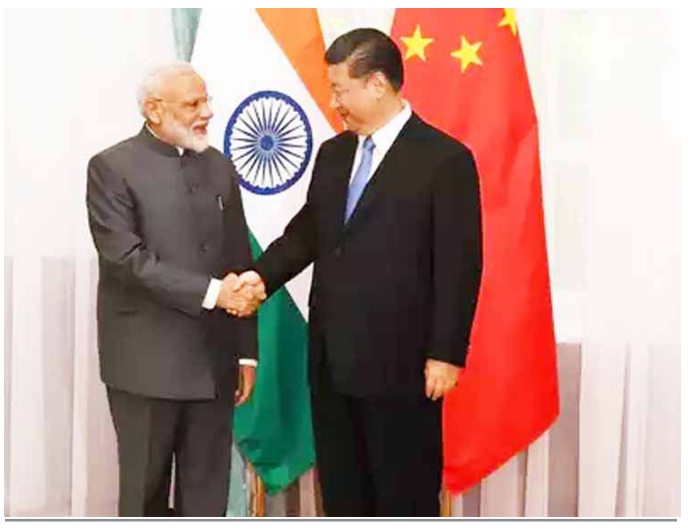

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

वॉशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस के एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने भारत के प्रति 'आक्रामक' विदेश नीति अपनाई है। साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट करने के प्रयासों को 'रोका' है जिससे शांति कायम करने में रुकावटें आई हैं। अमेरिकी रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले सात हफ्तों से पूर्वी लद्दाख के कई स्थानों पर गतिरोध बना हुआ है।

गत 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प में भारत के 20 सैन्यकर्मियों के शहीद होने के बाद तनाव और बढ़ गया है। 'अमेरिका–चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग' द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है, 'चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के महासचिव शी जिनपिंग के नेतृत्व में पेइचिंग ने नयी दिल्ली के प्रति आक्रामक विदेश नीति का रुख अपनाया है। 2013 से चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत के साथ पांच बड़े टकराव हुए हैं।'

रिपोर्ट में कहा गया है, 'पेइचिंग और नयी दिल्ली ने अपनी सीमाओं को स्थिर बनाने के लिए कई समझौते किए और परस्पर विश्वास पैदा करने के कदम उठाए लेकिन चीन ने एलएसी को स्पष्ट करने के प्रयासों को रोका जिससे शांति कायम करने में रुकावटें आयीं।' आयोग में सुरक्षा और विदेश मामलों की टीम के नीति विश्लेषक विल ग्रीन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सरकार अमेरिका और उसके सहयोगियों से भारत के मजबूत होते संबंधों को लेकर डरी हुई है।

इसमें कहा गया है कि 2012 में शी के सत्ता में आने के बाद से झड़पें बढ़ गई हैं जबकि उन्होंने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पेइचिंग तथा नयी दिल्ली तनाव को कम करने के लिए परस्पर विश्वास बहाली की कई व्यवस्थाओं पर सहमत हुए। रिपोर्ट के अनुसार 2013 से पहले सीमा पर आखिरी बड़ा टकराव 1987 में हुआ था। इसमें कहा गया है, '2020 की झड़प बीजिंग की आक्रामक विदेश नीति का परिणाम है।

यह झड़प ऐसे समय हुई है जब बीजिंग हिंद–प्रशांत क्षेत्र जैसे कि ताइवान और दक्षिण तथा पूर्वी चीन सागर पर संप्रभुता के अपने दावों पर आक्रामक रूप से जोर दे रहा है।'

चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, संसद में वोटिंग

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

वॉशिंगटन। अमेरिकी संसद ने चीन के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हॉन्ग कॉन्ग में चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लागू करने के खिलाफ अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी साथ आया है। इससे पहले सीनेट भी ऐसे बिल को मंजूरी दे चुका है। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि चीनी सरकार के इस कानून के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।

नैन्सी ने कहा कि इस कानून ने 'एक देश दो व्यवस्था' के सिद्धांत को खत्म किया है। उन्होंने कहा, 'आजादी से प्यार करने वाले सभी लोगों को इस भयानक कानून कि खिलाफत करनी चाहिए। अगर हम अपने व्यापारिक हितों के चलते चीन में मानवाधिकार के उल्लंघन पर नहीं बोलेंगे तो हम किसी और जगह पर भी इस मुद्दे पर बोलने के काबिल नहीं रहेंगे।'

सीनेट ने पिछले हफ्ते ऐसा ही बिल पास किया था लेकिन उसमें सीनेट ने कुछ बदलाव किए हैं। एक अधिकारी का कहना है कि सीनेट जल्द ही इसपर वोट करेगा। बता दें कि नए कानून पर चीन और अमेरिका के बीच बहस छिड़ी हुई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री माइक पोंपियो ने कहा था कि वह चीन के अधिकारियों पर वीजा बैन लगाएंगे। इसके बाद चीन ने भी इसी तरह की कार्रवाई की धमकी दी थी।

जापान की 'सुप्रीम' बुलेट ट्रेन, भूकंप के दौरान भी दौड़ती रहेगी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) टोक्यो। जापान में अब ऐसी बुलेट ट्रेन चलेगी जो न केवल तेज दौड़ेगी बल्कि भूकंप के दौरान भी यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखेगी। इस ट्रेन का नाम है–एन700एस इसके नाम में एस का मतलब है 'सुप्रीम।' यह ट्रेन टोक्यो से ओसाका शहर के बीच चलेगी। यह दुनिया की सबसे तेज स्पीड वाली ट्रेनों में से एक है। यह 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। सेंट्रल जापान रेलवे ने 13 साल बाद तोकैदो शिंकनसेन लाइन पर नया बुलेट ट्रेन मॉडल पटरी पर उतारा है। इस ट्रेन को ओलिंपिक खेलों के दौरान चलाया जाना था लेकिन कोरोना महामारी के चलते गेम्स नहीं हो पाए। बुलेट ट्रेन का यह मॉडल पिछली बुलेट ट्रेनों से ज्यादा अलग नहीं दिखाई देता।

भारत के ब्रह्मास्त्र से डरकर चीनी सेना ने लद्दाख में की घुसपैठ!

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

भारतीय वायुसेना का एस–400 डिफेंस सिस्टम लेना बड़ी वजह

मास्को। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 5 मई से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में कई जगहों पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। गत 15 जून की रात को गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद तनाव और बढ़ गया है। इस बीच रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन जल्द ही रूस से भारत को मिलने जा रहे एस–400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से डर गया है और इसीलिए उसने पूरी रणनीति के तहत यह कार्रवाई की है।

चीन एस–400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता रहा है और उसकी खूबियों से पूरी तरह से परिचित है। माना जा रहा है कि उसने भारत लद्दाख से लगती अपनी सीमा पर एस–300 और एस–400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। इसके जवाब में भारत ने भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लैस सुखोई फाइटर जेट को लद्दाख में तैनात कर दिया है।

भारतीय वायुसेना में रह चुके और रक्षा विशेषज्ञ विजेंदर के ठाकुर ने रूसी समाचार वेबसाइट स्पूतनिक न्यूज से कहा कि रणनीतिक और सामरिक फायदे के लिए सेना के बल पर वास्तविक नियंत्रण को बदलने का फैसला संभवतः राजनीतिक है लेकिन इसे अभी लेने के फैसले के पीछे एक खास मकसद छिपा हुआ है। इसके पीछे भारतीय वायुसेना का एस–400 डिफेंस सिस्टम लेना बड़ी वजह है।

ठाकुर ने कहा कि तिब्बत के पठारों की आमतौर पर ऊंचाई 4500 मीटर है और चीने के निचली उड़ान भर रहे एयरक्राफ्ट को 5 हजार मीटर की ऊंचाई से उड़ना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का एस–400 डिफेंस सिस्टम ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे चीनी फाइटर जेट और मध्य ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन आसानी से डिटेक्ट कर सकता है।

हांगकांग निवासियों को पनाह दे सकता है ऑस्ट्रेलिया

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें इस अर्द्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के कदम से खतरा है। मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनका मंत्रिमंडल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरह के ही अवसरों को मुहैया कराने पर जल्द ही विचार करेगा जिन्होंने हांगकांग वासियों को नागरिकता की पेशकश की है।

मॉरिसन ने पत्रकारों से कहा, ''जब हम इस पर अंतिम निर्णय ले लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि हम समर्थन देने की तैयारी कर रहे हैं? तो जवाब है रू हां।'' ब्रिटेन ब्रिटिश राष्ट्रीय विदेशी पासपोर्ट के पात्र हांगकांग के 30 लाख निवासियों को आवासन अधिकार दे रहा है जिससे वह पांच वर्षों के लिए ब्रिटेन में रह और काम कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया हांगकांग निवासियों को अस्थायी सुरक्षा वीजा दे सकता है जिससे वहां के शरणार्थी देश में तीन वर्षों तक रह सकेंगे।